[2021] 9 एस. सी. आर. 711

पार्वती देवी

बनाम्

बिहार राज्य अब झारखंड एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 574/2012)

17 दिसंबर, 2021

[एन. वी. रमना, भारत के मुख्य न्यायाधीश,

सूर्यकान्त और हिमा कोहली, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860: उपधारा 304 बी और 201 संयुक्त पठन धारा ..34-दहेज मृत्यु-अभियोजन का मामला यह था कि पीड़ित- वादी (अभियोजन साक्षी-3) की मृत पुत्री मुखबिर की शादी ए-1 से हुई थी-शादी के कुछ महीनों के भीतर, ए-1, उसके पिता (ए-2) और उसकी माँ (ए-3) उसे नकदी और मोटर साइकिल के लिए परेशान करना शुरू कर दिया -उन्होंने पीड़िता को धमकी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वे उसे वैवाहिक घर से बाहर फेंक देंगे और ए-1 की शादी किसी और से करवा देंगे-इसी तरह का संदेश पीडब्लू-3 को उसके दामाद (पीडब्लू-2) ने दिया था, जिसके साथ ए-1 ने अपर्याप्त दहेज का मुद्दा उठाया था-इस घटना के 15 दिनों के भीतर ही पीडब्लू-3 को पीडब्लू-2 से उसकी बेटी के वैवाहिक घर से लापता होने की जानकारी मिली थी-व्यर्थ तलाशी लेने के बाद स्थानीय पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई थी-शिकायत के पांच दिन बाद, नदी के किनारे से एक शव बरामद किया गया था-पीडब्लू-3 ने शव की पहचान उसकी बेटी के रूप में की-डॉक्टर जिसने शव परीक्षा किया था ने कहा कि शव पर मरणपूर्व किसी चोट का सबूत नहीं है। निचली अदालत ने परिस्थिजन्य साक्ष्य के आधार पर सभी आरोपियों को उपधारा 304 बी और 201 संयुक्त पठन धारा 34 के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा-दोषसिद्धि के खिलाफ अपील-ए-2 की अपील के लंबित रहने के दौरान

मृत्यु हो गई-आयोजितःधारा 304 बी में निर्धारित परिस्थितियों को इस तथ्य के आलोक में स्थापित किया गया था कि मृतकाअपनी शादी के कुछ महीनों के भीतर अपने वैवाहिक घर से लापता हो गई थी और उसके तुरंत बाद दहेज की मांग की गई थी और असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह की मृत्यु को "दहेज मृत्यु" के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए-ए-1 (मृतका के पति) को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत थे-परिस्थितियों को एक साथ रखते हुए, दहेज की मांगों को पूरा करने में विफल रहने पर शादी के कुछ महीनों के भीतर अपनी पत्नी के जीवन को समाप्त करने में उसके अपराध की ओर बिना किसी संदेह के इंगित किया गया-ए-1 पर लगाए गए विवादित निर्णय और सजा का आदेश बनाए रखा गया है-हालांकि, ए-3 (सास) के खिलाफ, साक्ष्य ने दहेज की मांगों के संबंध में उसके खिलाफ केवल सामान्य आरोपों को दिखाया-अभियोजन कोई विशिष्ट आरोप इंगित करने में सक्षम नहीं था, न ही उसके खिलाफ कोई विशिष्ट सबूत या गवाही देने में सक्षम था।

उसके खिलाफ दोषसिद्धि आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

मानाः 1.1 भा.दं.सं. की धारा 304 बी, जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के साथ पढ़ा जाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि एक बार जब अभियोजन पक्ष यह प्रदर्शित करने में सक्षम हो जाता है कि किसी महिला को उसकी मृत्यु से तुरंत पहले दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, तो न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़ेगा कि जिन व्यक्तियों ने उसे दहेज के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया है, उन्होने भा.दं.सं. की धारा 304 बी के अर्थ के तहत दहेज मृत्यु का कारण बनी है। तथापि, उक्त अनुमान यह है कि खंडन योग्य और अभियुक्त के ठोस साक्ष्य के माध्यम से प्रदर्शित करने में सक्षम होने पर खारिज किया जा सकता है कि भा.दं.सं. की धारा 304 बी के सभी अवयवों को संतुष्ट नहीं किया गया है। [पारा 17] [722-सी-ई]

बंसी लाल बनाम हरियाणा राज्य (2011) 11 एस. सी. सी. 359 [2011] 1 एससीआर 724; माया देवी और अन्य बनामहरियाणा राज्य

(2015) 17 एससीसी 405:[2015] 11 एस. सी. आर. 903-पर निर्भर था।

1.2 तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा की गई घटिया जांच के बावजूद, परिस्थितियों में भा.दं.सं. की धारा 304 बी इस तथ्य के आलोक में स्थापित की गई है कि मृतक, अपनी शादी के कुछ महीनों के भीतर अपने वैवाहिक घर से लापता हो गई थी और उस पर तुरंत ही दहेज की मांग शुरु हो गई थी एवं उसकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई इस तरह की मृत्यु को "दहेज मृत्यु" के रूप में चिह्नित करना होगा। [पारा 18] [722-ई-एफ]

2. नदी के किनारे से शव की बरामदगी स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि मृतक महिला की असामान्य परिस्थिति में मृत्यु हो गई थी, ऐसी परिस्थितियाँ जिन्हें केवल उसके पति और ससुराल वाले ही समझा सकते थे, क्योंकि वह अपने वैवाहिक घर में रह रही थी जब वह अचानक गायब हो गई और उसके लापता होने के लिए कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अभियुक्त की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि बराकर नदी के तट से बरामद शव की पहचान नहीं की जा सकती है, यह गुणों से रहित है जब मृतका के पिता पीडब्लू-3 ने गवाही दी कि वह मृत शरीर को मृतक के रूप में पहचान सकते हैं, चेहरे के एक हिस्से से जो बरकरार था और शरीर पर पाए गए कपड़ों से। जहाँ तक ए-1 का संबंध है, उच्च न्यायालय और निचली अदालत साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत उसके खिलाफ सही अनुमान लगाया है, जो यह निर्धारित करता है कि अदालत यह मान लेगी कि किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है यदि यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले, उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया हो। [पारा 19] [722-एफ-एच; 723-ए-बी]

3. 1.अभियोजन पक्ष का मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। कोई चश्मदीद गवाह पेश नहीं किया गया जो यह गवाही दे सके कि मृतका का शव बराकर नदी के तट पर कैसे मिला था। परिस्थितियों से, दो परिकल्पनाएँ हो सकती है। एक तो यह है कि मृतका को उसके ससुराल की चारदीवारी के भीतर मार दिया गया था, उसके शव को गोपनीय ढंग से बाहर नदी में फेंक दिया गया था। दूसरा पूर्वधारणा ऐसा माना जा सकता है

कि मृतका जीवित थी जब उसे किसी बहाने से नदी के किनारे ले जाया गया और नदी में धकेल दिया गया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। यदि पहली धारणा को सही माना जाता है, तो निश्चित रूप से, कुछ ग्रामीणों ने आरोपी व्यक्तियों को शव को नदी में ले जाते हुए देखा होगा जहां उसे अंततः फेंक दिया गया था।हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने किसी भी ग्रामीण को पेश नहीं किया है जो मृतका के शव को वैवाहिक घर से बाहर निकालकर नदी में ले जाने का गवाह था।इसलिए, इस संस्करण को दूसरे के पक्ष में त्यागना होगा जो यह है कि मृतका जीवित थी, जब उसे नदी में ले जाया गया था और फिर उसे जबरन अंदर धकेल दिया गया था और वह पानी से भरी कब्र से जीवित नहीं निकल सकी।बाद की धारणा को शव परीक्षा-प्रतिवेदन से भी ताकत मिलती है जो दर्ज करती है कि शरीर पर किसी भी मृत्यु पूर्व चोट के कोई संकेत नहीं थे।यदि मृतका को घर में मार दिया जाता, तो शरीर पर संघर्ष के कुछ निशान अवश्य निकलते। [पारा 21] [723-ई-एच- 724-ए.बी.]

3.2 ए-1 (मृतक के पति) को शामिल करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सबूत लाए गए है। परिस्थितियों को एक साथ रखते हुए, दहेज की मांगों को पूरा करने में विफल रहने पर शादी के कुछ महीनों के भीतर अपनी पत्नी के जीवन को समाप्त करने में उसके अपराध को बिना किसी संदेह के इंगित करता है। ए-1 पर लगाए गए विवादित निर्णय और सजा का आदेश हस्तक्षेप के योग्य नहीं है और इसे बनाए रखा जाता है। [पारा 22] [724-बी-सी]

3.3 जहां तक ए-3 (सास) की बात है, अभिलेख पर साक्ष्य से दहेज की माँग के संबंध में उसके खिलाफ केवल कुछ सामान्य आरोप लगाए गए हैं। प्रत्यर्थी-राज्य किसी विशिष्ट आरोप का संकेत नहीं दे पाया है, न ही उसके खिलाफ किसी विशिष्ट साक्ष्य या गवाही इंगित कर पाया है। वास्तव में, अदालत के समक्ष एकमात्र प्रत्यक्ष साक्ष्य में, पीडब्लू-3 (मुखबिर और पीड़ित के पिता) ने उल्लेख किया है कि ए-2 ने मृतका को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 बी और 201 के तहत अपराध के लिए ए-3 को दोषी ठहराने वाले न्यायालयों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जाता है।यदि किसी अन्य मामले में हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। [पारा 23] [724-डी-एफ]

जी. वी. सिद्धरमेश बनाम कर्नाटक राज्य (2010) 3 एस. सी. सी. 152:[2010] 2 एससीआर 380; अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(2010) 12 एससीसी 350:[2010] 7 एस. सी. आर. 1119- संदर्भित

वाद कानून संदर्भ

| | | |
|---|---|---|
| [2011] 1 एससीआर 724 | पारा 15 पर | निर्भर किया गया। |
| [2015] 11 एससीआर 903 | पारा 16 पर | निर्भर किया गया। |
| [2010] 2 एससीआर 380 | पारा 16 पर | निर्भर किया गया। |
| [2010] 7 एससीआर 1119 | पारा 16 पर | निर्भर किया गया। |

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 574/2012

आपराधिक अपील सं. 345/1999 (आर) में झारखंड उच्च न्यायालय रांची के दिनांकित 01.05.2007 के निर्णय और आदेश से।

साथ में

आपराधिक अपील सं. 575/2012

आभास परिमल, सोमनाथ पधान, सत्य काम शर्मा, सुश्री अनघा एस. देसाई, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

तपेश कुमार सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, श्रीमती एल. भास्वती सिंह, आदित्य नारायण दास, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय हिमा कोहली, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

निर्णय

1. राम सहाय महतो, आपराधिक अपील संख्या 575/2012 (जिसे इसमें इसके बाद ए-1 कहा गया है) में अपीलकर्ता और उसकी मां पार्वती देवी, आपराधिक अपील संख्या 574/2012 (इसमें इसके बाद) में अपीलकर्ता (जिसे ए-3 के रूप में निर्दिष्ट किया

गया है) वे झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 मई, 2007 को पारित सामान्य निर्णय से व्यथित हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख और 201 के साथ पठित धारा 34 के तहत अवर सत्र न्यायधीश, पंचम, गिरीडीह के दिनांक 20 सितंबर, 1999 के दो-सिद्धि के निर्णय को बरकरार रखा गया है, जो उन्हें और नीमा महतो (ए-1 के पिता और ए-3 के पति) को दोनों दंडादेशों के साथ प्रत्येक गणना पर क्रमशः दस वर्ष और तीन वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा। रिकॉर्ड के लिए, नेमा महतो ने 2009 की एसएलपी (सीआरएल) नं. 6955 के रूप में पंजीकृत एक अपील भी पेश की थी, जो उसके लंबित रहने के दौरान समाप्त होने पर समाप्त हो गई थी।

2. अभियोजन का मामला, जैसा कि आक्षेपित निर्णय से कहा गया है, यह है कि मुखबिर, बोधी महतो (पीडब्लू-3) ने अपनी बेटी, फुलवा देवी की शादी वर्ष 1997 में राम सहाय महतो (ए-1) से की थी और विवाह के कुछ महीनों के भीतर, ए-1, उसके पिता नीमा महतो (मृत होने के बाद) और मां, पार्वती देवी (ए-3) ने फुलवा देवी को 20,000/- रुपये नकद और एक राजदूत मोटर साइकिल के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था। अपनी मांगों को पूरा करने में उसके माता-पिता की असमर्थता व्यक्त करने पर, उसे क्रूरता से पीटा गया और धमकी दी गई कि ए-1 की शादी किसी और लड़की से हो जाएगी। इसके बाद, यह सूचना मिलने पर कि उनकी बेटी अपने ससुराल से गायब हो गई है, पी. डब्ल्यू. 3 उसके घर पहुंचा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, उसने बिरनी पुलिस स्टेशन में जाकर लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय पुलिस द्वारा 8 अगस्त, 1997 को भारतीय दंड संहिता की धारा 304/201/34 के तहत अपराधों के लिए ए-1, ए-2 और ए-3 के विरुद्ध 1997 का मामला संख्या 71 दर्ज किया गया था।

3. अनुसंधान की समाप्ति पर दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 सहि उपरोक्त अपराधों के लिए सभी तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया। 13 अगस्त, 1997 को पीडब्लू-3 द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के पांच दिनों के बाद, बाराकर नदी के तट से एक कंकाल बरामद किया गया, जो ग्राम सिरमाडीह से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर था, जिसे फुलवा देवी माना गया था। तीन अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी/34,201/34 के तहत आरोप तय किए गए। अभियोजन ने अभियुक्त का दोष-सिद्ध करने के लिए सात गवाहों का बयान लिया गया जबकि

अभियुक्तों ने छः गवाहों का बयान दर्ज करवाये। अभियोजन पक्ष द्वारा जिन गवाहों से पूछताछ की गई उसमें डॉ. बी० पी० सिंह, चिकित्सक जिसने शव का अंत्यपरीक्षण किया या, सहदेव महतो (पीडब्लू-2), मृतक के बहनोई बोधी महतो (पीडब्लू-3), मृतक के पिता और मुखबिर जोगेश्वर महतो (पीडब्लू-4), मृतक के भाई, पीडब्लू-4 टीकी देवी (पीडब्लू-5) पी डब्लू 4 की पत्नी (मृतक की साली/भाभी) और जांच अधिकारी सुरेश प्रसाद सिंह (पीडब्लू-6) शामिल थे।

4. उपर्युक्त गवाहों के बयानों के गहन विश्लेषण के बाद उच्च न्यायालय ने उनकी गवाही को संक्षेप में प्रस्तुत किया। डॉ. भूपेंद्र प्रसाद सिंह (पीडब्लू-1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने उनके सामने पेश किए गए मृत शरीर का शव परीक्षा फुलवा देवी के रूप में किया था और शव को अत्यधिक विघटित पाया। बायां पैर, बायां हाथ और बायां हाथ गायब था। इसी तरह दाहिने ऊपरी अंग और दाहिने निचले अंग घुटने के जोड़ के नीचे नहीं थे। अंत्यपरीक्षण के बाद किसी तरह की चोट के सबूत नहीं मिले हैं। अंत्यपरीक्षण होने तक जो समय बीत गया था, उसका मूल्यांकन एक सप्ताह के रूप में किया गया था।

5. मृतक के मुखबिर और पिता बोधी महतो (पीडब्लू-3) ने गवाही दी कि उसकी मृत बेटी की शादी ए-1 से हुई थी और उसकी शादी के कुछ महीनों के भीतर, आरोपी ने उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया और उसके माता-पिता द्वारा दिए गए अपर्याप्त दहेज के बारे में शिकायत की।उन्होंने उसकी बेटी से 20 हजार रुपये नकद और एक राजदूत मोटर साइकिल की मांग की थी और धमकी दी थी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। फुलवा देवी ने अतिरिक्त दहेज की यह मांग अपने माता-पिता, भाई और भाभी के साथ साझा की थी। इसी तरह का एक संदेश उसके दामाद सहदेव महतो (पीडब्लू-2) द्वारा पीडब्लू-3 को दिया गया था, जिसके साथ आरोपी ने अपर्याप्त दहेज का मुद्दा उठाया था।पीडब्लू-3 ने बयान दिया कि जब वह 'अशर' के महीने में अपनी बेटी के ससुराल में गया था, तो ए-1 और उसके पिता (ए-2, अब मृतक) ने उसे आगाह किया था कि अगर उसने उनकी मांग पूरी नहीं की, तो वे फुलवा देवी को वैवाहिक घर से बाहर फेंक देंगे और किसी और से ए-1 शादी कर लेंगे।यह पूर्वोक्त घटना के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर था कि पीडब्ल्यू-3 को पीडब्ल्यू-2 से सूचना मिली कि उसकी बेटी अपने ससुराल से गायब हो गई है। उसके ससुराल पर दौड़ने और उसे हर जगह ढूंढने पर, जब उसका पता

नहीं लगाया जा सका, स्थानीय पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज की गई क्योंकि पी डब्लू-३ ने कहा कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि अभियुक्त ने उसकी हत्या की और कहीं-न-कहीं उसके शरीर को छिपाया। शिकायत दर्ज करने के पांच दिनों के बाद ही मृतक का शव बरामद किया गया।पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 उस स्थान पर गए जहां मृत शरीर बरामद किया गया था।चेहरा देखकर जो आंशिक अक्षुण्ण था और कपड़ों की पहचान करके, पीडब्ल्यू-3 ने शव की पहचान अपनी बेटी के रूप में की।अभियुक्त की ओर से की गई जिरह में, पीडब्लू-३ अपनी गवाही पर खरा उतरा, जो अडिग बना रहा.

6. पीडब्लू-3 के दामाद सहदेव महतो (पीडब्लू-2) और पीडब्लू-3 के पुत्र जोगेश्वर महतो (पीडब्लू-4) ने पीडब्लू-3 के समान ही साक्ष्य दिए।उन्होंने कहा कि फुलवा देवी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था और उससे दहेज की मांग करने के अलावा, उसे धमकी दी गई थी कि यदि दहेज की मांग पूरी नहीं की गई, तो उसके पति का फिर से किसी और से विवाह हो जाएगा।पीडब्लू-4 ने कहा कि अपने माता-पिता के घर के दौरे के दौरान, फुलवा देवी ने अपने परिवार के सदस्यों को सभी अभियुक्तों द्वारा की गई दहेज की मांगों के बारे में बताया था कि उन्हें धमकी दी गई थी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे अपने पुत्र, ए-1 की दूसरी शादी करेंगे।

7. दोनों गवाहों ने बताया कि उन्हें मृतक के अपने ससुराल से लापता होने के बारे में कैसे पता चला। पीडब्लू-2 ने बयान दिया कि उसे तीसरे पक्षों से पता चला कि फुलवा देवी अपने ससुराल से गायब है और उसकी हत्या के बाद उसके शव को बराकर नदी में फेंक दिया गया था। उसने तुरंत अपने ससुर पीडब्ल्यू-3 को सूचित किया जो नदी के किनारे अपनी बेटी की तलाश में निकले थे। पीडब्लू-3 ने अपने दामाद पीडब्लू-2 और अपने पुत्र पीडब्लू-4 के साथ गहन तलाशी ली और पुलिस को भी सूचित किया। पास की नदी के किनारे से एक शव को बरामद करने और उनके द्वारा फुलवा देवी के रूप में शव की पहचान के पहलू पर दोनों गवाहों के शेष संस्करण, एक दूसरे की पुष्टि के साथ सुसंगत रहे।

8. उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि सहदेव महतो, पीडब्लू-2 का साक्ष्य इस हद तक प्रासंगिक है कि उसकी मृत्यु से पहले फुलवा देवी ने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उस पर की गई दहेज की मांग के बारे में उससे बात की थी। वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन उसने कहा कि उसे एक ग्रामीण से पता चला कि फुलवा देवी के शव

को आरोपी द्वारा हत्या करने के बाद बराकर नदी में फेंक दिया गया था। उक्त गवाह मृतक महिला के कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान फुलवा देवी के रूप में की गई थी। जोगेश्वर महतो, पीडब्लू-4 ने दहेज की मांग के पहलू पर अपने पिता, पीडब्लू-3 की गवाही की पुष्टि की है और तथ्य यह है कि फुलवा देवी ने अपनी एक यात्रा के दौरान अपने माता-पिता के घर पर यह बताया था।सभी तीनों गवाहों ने एक समान रुख अपनाया कि दहेज की मांग उस समय के करीब की गई थी जब वह अपने ससुराल से गायब हो गई थी और वह अपने ससुराल में अंतिम बार रह रही थी जब वह अचानक एक अच्छा दिन पहले गायब हो गई थी।

9. उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी सुरेश प्रसाद सिंह (पीडब्लू-6) द्वारा जांच किए जाने के तरीके पर प्रतिकूल टिप्पणी की हैजिसने गवाहों के बयान दर्ज किए, फुलवा देवी की जांच रिपोर्ट तैयार की, घटना के दो स्थानों के बारे में प्रमाणित किया-ग्राम करनी और बाराकर नदी के तट पर मृत व्यक्ति का वैवाहिक घर, जहां शव पाया गया था, लेकिन ग्राम के किसी भी निवासी का बयान दर्ज करने में विफल रहे, जिसमें पड़ोसियों के बयान सहित केवल पच्चीस घर शामिल थे न ही उसने मृतक के शव का पता लगाने के लिए कोई ठोस प्रयास किया।यह केवल मृतक के पिता, भाई और बहनोई क्रमशःपीडब्लू-3, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-2 के द्वारा किये गए निरंतर प्रयास था कि जिस दिन फुलवा देवी अपने ससुराल से गायब हो गई थी, उसके लगभग एक सप्ताह के बाद शव अंततः मिला था, उस समय तक शरीर काफी हद तक सड़ चुका था।

10. परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला को उस बिंदु से जोड़ते हुए जब फुलवा देवी ने अपने माता-पिता और संबंधियों को अभियुक्त द्वारा अपने विवाह के कुछ महीनों के भीतर उस अवस्था तक उस पर की गई दहेज की मांगों के बारे में सूचित किया था, जब वह अचानक अपने ससुराल से गायब हो गई थी और अंत में, जब उसका शव बराकर नदी के तट पर बरामद किया गया था, उच्च न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को निम्नलिखित आधार पर दोषारोपित करने के लिए निचली अदालत द्वारा दिये गए निष्कर्षों से सहमति व्यक्त कीः

> "(i) मृतक फुलवा देवी का विवाह नेमा महतो और पार्वती देवी के पुत्र राम सहाय महतो के साथ मृत्यु के सात वर्षों के भीतर हआ था।

(ii) मृतक का शव 13.8.97 को बराकर नदी में पाया गया था और इसके सुसंगत साक्ष्य हैं कि मृतक सामान्य परिस्थिति से अलग ढंग में भरी

(iii) मृतक अपनी मृत्यु से पहले अपने ससुराल में थी।

(iv) मृतक का कोई अता-पता नहीं था लेकिन न तो उसके माता-पिता को कोई सूचना दी गई और न ही पुलिस को कोई सूचना दी गई।

(v) मृतक को आरोपी व्यक्तियों, जो पति और उसके अन्य रिश्तेदार हैं, द्वारा हमला और उत्पीड़न किया गया था।

(vi) ऐसी क्रूरता और उत्पीड़न दहेज की मांग के संबंध में था।

(vii) ऐसी क्रूरता और उत्पीड़न उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया गया था।"

11. उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा व्यक्त इस विचार से सहमति व्यक्त की कि अभियुक्त उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने में बुरी तरह विफल रहे हैं जिनके तहत मृतक अपने ससुराल से गायब हो गई थी और उसने अभियुक्त द्वारा स्थापित बचाव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है कि वह अपने पति और सास-ससुर के साथ नहीं रह रही थी बल्कि वह अपने बहनोई, पीडब्लू-2 के साथ रह रही थी। आरोपी द्वारा ली गई एक अन्य दलील कि बाराकर नदी के किनारे से बरामद मृत शरीर की पहचान नहीं की जा सकती थी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि आरोपी उस परिस्थिति को समझाने में विफल रहा जिसमें मृतक अपने ससुराल से गायब हो गई और उसका कोई पता नहीं चला.दोषी व्यक्ति का आचरण मृतक के ससुराल से लापता होने के बारे में उसके परिवार के सदस्यों या पुलिस को सूचित करना और उसकी तलाश करने के लिए उनकी ओर से कोई प्रयास करने में उनकी विफलता भी अभियुक्त के आचरण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।वास्तव में, मृतक के भाई पीडब्लू-४ ने स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि जब वह उसके ससुराल गया था, तो उसने इसे बंद पाया और सभी आरोपी घटना के तुरंत बाद फरार हो गए थे जो उनके खिलाफ एक गंभीर परिस्थिति थी।

12. अभियोजन के मामले और अभियुक्त द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की जांच करने के लिए, हम भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के सुसंगत उपबंध के नीचे उद्धृत कर सकते हैं जो दहेज मृत्यु से संबंधित हैः- -

> "304B दहेज मृत्यु - (1) जहां किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी जलने या शारीरिक क्षति के कारण होती है या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न होती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या तंग किया गया था, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसे पति या नातेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।
>
> व्याख्या - इस उपधारा के प्रयोजन के लिए " दहेज " का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।
>
> (2) जो कोई दहेज हत्या करेगा, उसे कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी।"

13. जैसा कि पूर्वोक्त उपबंध से देखा जा सकता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराने के लिए निम्नलिखित पूर्वापेक्षाएं पूरी की जानी चाहिएः

(i) किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न किसी कारण से हुई होगी।

(ii) ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष की अवधि के भीतर हुई होगी

(iii) मृत्यु से ठीक पहले महिला को उसके पति के हाथों क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा होगा, और

(iv) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की किसी मांग के लिए या उससे संबंधित होना चाहिए।

14. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख के बाद आने वाले मामले में दहेज मृत्यु से संबंधित उपधारणा का उल्लेख किया गया है और इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया गया हैः-

> " 113B. दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा -
>
> जब प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीडन किया गया है तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।
>
> स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, '' दहेज मृत्यु '' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304-ख में है।"

भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी से संलग्न स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 'दहेज' शब्द का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में दिया गया है, जो इस प्रकार हैः

> "2. 'दहेज' की परिभाषा-इस अधिनियम में,
>
> "दहेज" "से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या दी जाने के लिए सहमत कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है-"
>
> (क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार से विवाह किए जाने पर या
>
> (ख) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में;

विवाह पर या उससे पहले या उसके बाद किसी भी समय, किंतु ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) लागू होता है, दहेज या महर शामिल नहीं है।"

15. पूर्वोक्त उपबंधों के आयात को इस न्यायालय के कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है।बंसीलाल बनाम हरियाणा राज्य[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः

> "17. धारा 498-क (धारा 304-ख) के तहत मामले पर विचार करते समय, क्रूरता मृत्यु के समय के निकट होने के दौरान साबित की जानी चाहिए और यह आरोपी द्वारा निरंतर और इस तरह का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न मृतक के जीवन को दयनीय बनाने वाला हो जो उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है।"

16. माया देवी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य[2] के मामले मे यह अभिनिर्धारित किया किः

> "23. धारा 304-ख के उपबंधों को आकर्षित करने के लिए, अपराध का एक मुख्य घटक, जिसे स्थापित किया जाना अपेक्षित है, यह है कि" "उसकी मृत्यु से ठीक पहले" "उसे दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था।" भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी में प्रयुक्त 'उसकी मृत्यु से पहले' अभिव्यक्ति निकटता परीक्षण के विचार के साथ मौजूद है। वास्तव में, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि दहेज और उत्पीड़न की कथित मांग के लिए कोई निकटता नहीं है। कथित दावे के संबंध में, हम अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विचार करते समय इसका उल्लेख करेंगे.यद्यपि प्रयुक्त भाषा 'उसकी मृत्यु से ठीक पहले' है, कोई निश्चित अवधि अधिनियमित नहीं की गई है और 'उसकी मृत्यु से ठीक पहले' अभिव्यक्ति

---

1 (2011) 11 एससीसी 359

2 (2015) 17 एससीसी 405

को दोनों अधिनियमितियों में परिभाषित नहीं किया गया है। तदनुसार, उसकी मृत्यु से पहले की अवधि का निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालयों द्वारा किया जाना है। तथापि, उक्त अभिव्यक्ति का सामान्य रूप से यह अर्थ होगा कि अंतराल संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न और प्रश्नगत मृत्यु के बीच अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच निकटतम और जीवंत संबंध होना चाहिए।यदि क्रूरता की कथित घटना समय से दूर है और संबंधित महिलाओं के मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त रूप से पुरानी हो गई है, तो इसका कोई महत्व नहीं होगा।"

[जी. वी. सिद्धरमैया बनाम कर्नाटक राज्य[3] और अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य[4] भी देखें]

17. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख के साथ पठित भा. दं. सं. की धारा 304 ख इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती कि एक बार जब अभियोजन यह प्रदर्शित करने में समर्थ हो जाता है कि किसी महिला को उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या तंग किया गया है, तो न्यायालय इस उपधारणा पर आगे बढ़ेगा कि उन व्यक्तियों ने, जिन्होंने दहेज की मांग के संबंध में उसे क्रूरता या तंग किया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के अर्थ के भीतर दहेज मृत्यु कारित की है। हालाँकि कथित उपधारणा खंडन योग्य है और अभियुक्त द्वारा पुख्ता प्रमाण के माध्यम से प्रदर्शित में सक्षम होने पर इस दूर किया जा सकता है कि भा. द. सं. की धारा के सभी तत्व संतुष्ट नहीं किए गए है।

18. वर्तमान मामले में, अभियोजन द्वारा किए गए घटिया जांच के बावजूद, हमारा मानना है कि आईपीसी की धारा 304 बी में दी गई परिस्थितियों को इस तथ्य के प्रकाश में स्थापित किया गया है कि मृतक, फुलवा देवी अपने विवाह के कुछ ही महीनों के भीतर अपने

3 (2010) 3 एससीसी 152

4 (2010) 12 एससीसी 350

ससुराल से गायब हो गई थी और दहेज की मांगों के तुरंत बाद और उसकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई थी, इस तरह की मृत्यु को दहेज मृत्यु के रूप में चरितार्थ करना होगा।

19. नदी के किनारे से शव की बरामदगी से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि फुलवा देवी की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिसे केवल उनके पति और ससुराल वालों द्वारा ही समझाया जा सकता था, क्योंकि वह अपने ससुराल में रह रही थी, जब वह अचानक गायब हो गई और उसके लापता होने के लिए कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। आरोपी की ओर से दलील दी गई कि बराकर नदी के किनारे से बरामद शव की पहचान नहीं की जा सकती है, जब मृतक के पिता पीडब्ल्यू-3 ने गवाही दी कि वह मृत शरीर को फुलवा देवी के रूप में पहचान सकता है, चेहरे के एक हिस्से से जो बरकरार था और शरीर पर पाए गए कपड़ों से। जहां तक ए-1 का संबंध है, उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत उसके खिलाफ एक उपधारणा बनाई है, जो निर्धारित करती है कि अदालत यह मान लेगी कि किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज मृत्यु कराई है, अगर यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ ही समय पहले, उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या तंग किया जाता था। ए-3 के खिलाफ यह कहां तक हो सकता है, इस पर बाद में चर्चा की जाएगी।

20. ए-1 द्वारा यह अभिवाक किया गया था कि वह घटना के समय ग्राम में मौजूद नहीं था और कोलकाता में था, जिसे योग्यता रहित होने के कारण उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है।इसी तरह, बाबूलाल यादव, डीडब्ल्यू-3 और बासुदेव महतो, डीडब्ल्यू-4 की गवाही अस्वीकार कर दी गई, खास कर क्योंकि डीडब्ल्यू-3 ने ए-1 के चाचा होने का दावा किया था, लेकिन वह अपने भतीजे की पत्नी का नाम भी नहीं दे सका और ए-1 के चचेरे भाई डीडब्ल्यू-4 ने बयान दिया था कि उसे अपनी शादी के बारे में पता नहीं था या उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी या वह जीवित थी।दोनों में से कोई भी गवाह अपने इस रुख के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर सका कि संबंधित समय पर ए-1 कोलकाता में प्रस्तुत रहा था।डीडब्ल्यू-6, कौटेश्वर यादव, जो उस ग्राम का रहने वाला है जहां कथित आरोपी रहता था, लेकिन उसने यह बयान दिया है कि वह खुद इसका स्थायी निवासी नहीं है, मृतक और उसके देवर, सहदेव महतो (पीडब्ल्यू-2) के बीच एक अवैध

संबंध स्थापित करने या वह उसके साथ रह रही थी और अपने ससुराल में नहीं रह रही थी को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा।

21. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभियोजन का मामला केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है। कोई चश्मदीद गवाह पेश नहीं किया गया है जो यह गवाही दे सके कि मृतक का शव बराकर नदी के तट पर कैसे पाया गया था.ऊपर वर्णित परिस्थितियों से, दो परिकल्पना की जा सकती है।एक तो यह है कि मृतक को उसके ससुराल की चार दीवारों के भीतर मार दिया गया था, उसके शव को गोपनीय ढंग से बाहर नदी में फेंक दिया गया था। दूसरा पूर्वानुमान यह होगा कि मृतक जीवित था जब उसे किसी बहाने से नदी के किनारे ले जाया गया और अंदर धकेल दिया गया तो डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। यदि पहली धारणा सही मानी जाती है, तो निश्चित रूप से किसी ग्रामीण ने आरोपी व्यक्तियों को मृत शरीर को नदी में ले जाते हुए देखा होगा जहां उसे आखिरकार फेंक दिया गया था। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई ग्रामीण पेश नहीं किया है जो मृतक के शव को वैवाहिक घर से बाहर ले जाकर नदी में ले जाए जाने का गवाह था। इसलिए, इस संस्करण को दूसरे संस्करण के पक्ष में खारिज कर दिया जाना चाहिए, जो यह है कि मृतक जीवित था, जब वह नदी के पास थी और फिर उसे जबरन अंदर धकेल दिया गया और जलीय समाधि से जीवित नहीं निकल सकी। बाद की धारणा को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से भी ताकत मिलती है, जिसमें दर्ज है कि शरीर पर पोस्टमॉर्टम से पहले किसी भी चोट के कोई संकेत नहीं थे। अगर मृतक को घर में मारा गया होता, तो शरीर निश्चित रूप से संघर्ष के कुछ संकेत देता।

22. राम सहाय महतो, ए-1 (मृतक के पति) पर अभियोग लगाने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य लाया गया है। परिस्थितियां एक साथ, दहेज की मांगों को पूरा करने में विफल रहने पर विवाह के कुछ महीनों के भीतर अपनी पत्नी के जीवन को समाप्त करने में उसके अपराध की ओर निर्विवाद रूप से संकेत करती हैं। हमारे विचार में, ए-1 पर अधिरोपित आक्षेपित निर्णय और दंडादेश का आदेश हस्तक्षेप के योग्य नहीं है और इसे बनाए रखा जाता है। ए-1 द्वारा दायर 2012 की आपराधिक अपील संख्या 575 तदनुसार खारिज की जाती है। वर्तमान में जमानत पर चल रहे अपीलकर्ता को अपनी सजा की शेष अवधि गुजारने के लिए चार सप्ताह के भीतर निचली अदालत/जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

23. जहां तक पार्वती देवी (सास) का संबंध है, अभिलेख पर साक्ष्य से उसके विरुद्ध दहेज मांगों के संबंध में केवल कतिपय सर्वव्यापी अभिकथन किए गए हैं। प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता न तो उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट अभिकथन इंगित कर पाया है और न ही कोई विशिष्ट साक्ष्य या परिसाक्ष्य इंगित कर पाया है। वास्तव में, न्यायालय के समक्ष एकमात्र प्रत्यक्ष साक्ष्य में, पीडब्लू-3 (पीड़ित के मुखबिर और पिता) उल्लेख करता है कि ए-2 ने मृतक को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी.उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और धारा 34 के साथ पठित धारा 201 के तहत अपराध के लिए ए-3 (2012 की आपराधिक अपील संख्या 574 में अपीलकर्ता) को दोषी ठहराने वाले निचले न्यायालयों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना आवश्यक है। यदि किसी अन्य मामले में उन्हें हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

[एन. वी. रमण], भारत के मुख्य न्यायाधीश

[सूर्य कांत],न्यायमूर्ति

(हिमा कोहली), न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

17 दिसंबर, 2021

**खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**